(iii) M|S. Chetak Construction Ltd., Indore.

(c) The work has not been awarded.

(d) Does not arise.

(e) Yes, Sir.

(f) All tenders have been rejected.

Designing and engineering of new public sector fertilizer plants

812. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

SHRI SUSHIL CHAND MOHUNTA:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Snam Progetti of Italy has virtually taken over the designing and engineering of the new public sector fertiliser plants in the country and that the Project and Development India Ltd. (PDIL) has expressed its concern about it to Government;

(b) if so, what are the reasons for handling over the entire designing and engineering of the new public sector fertiliser plants to an Italian firm; and

(c) to what extent Indian companies are likely to be affected as a result thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF FERTILIZERS (SHRI K. NATWAR SINGH): (a) to (c) Snamprogetti of Italy has provided basic engineering packages for Urea plant for the 2 public sector gas-based fertilizer projects at Thal in Maharashtra and Guna in Madhya Pradesh. The detailed engineering, supervision in construction work, procurement services, etc., were|are mostly being provided by Projects & Development India Ltd. (PDIL), a public sector engineering and consultancy organisation.

तिलहन के उत्पादन में आत्म-निर्भरता

813. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तिलहन के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने और खाद्य तेलों के आयात की मात्रा (मीट्रिक टनों में) में कमी करने के लिए अभी तक क्या उपाय किये गए है ;

(ख) क्या यह सच है कि शुरू में आयात किये गये तेल का मूल्य 4 रुपये प्रति किलोग्राम था जो अब बढ़कर 8 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक हो गया है जबकि आयात की गयी कुल मात्रा के आधे से भी अधिक है ; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए गठित की गयी तकनीकी समिति में शामिल किए गए व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उन्हें क्या कार्य सौंपा गया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) देश में तिलहनों के उत्पादन में भरपूर वृद्धि करने की दृष्टि से तिलहन उगाने वाले 17 राज्यों में 1984-85 से केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना शुरू की गई है। इसी प्रकार, भारत सरकार ने खाद्य तेलों के आयात को कम से कम करने के लिये अनेक उपाय किये हैं, अर्थात सार्वजनिक वितरण पद्धति/छोटे पैकों की योजना के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और वनस्पति उद्योग को आयातित खाद्य तेलों के आवन्टन में कमी करना, आयातित खाद्य तेलों के निर्गम मूल्यों में वृद्धि करना वनस्पति के विनिर्माण में विकर्षक सरसों के तेल और विलायक के प्रयोग द्वारा निकाले गये तेलों का उपयोग, गौण तेल के उपयोग पर उत्पाद शुल्क में रियायत, वनस्पति के विनिर्माण के लिये "साल" वसा का उपयोग, तिलहनों की उत्पादकता में वृद्धि करने

के लिये अनुसंधान संबंधी प्रयासों को तेज करना और तिलहन उत्पादन कार्यक्रम को गति के साथ-साथ चलने के लिये परिसंस्करण और अवसंरचना संबंधी सुविधाओं की स्थापना करना आदि।

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा खरीद अपने यहां पंजीकृत अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिष्ठित सप्लायरों से निविदाएं आमन्त्रित करने के बाद ही की जाती है। खाद्य तेलों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में काफी उतार-चढ़ाव आता रहता है, जो विश्व की सप्लाई और मांग की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं, अर्थात् मौसम की स्थितियों, बाजार में लगे घन और अन्य फसलों की उपलब्धि आदि, पर निर्भर करता है।

अतः, खाद्य तेलों के आयात मूल्य में भी काफी उतार-चढ़ाव आता रहता है। कितना किया जाये इसका निर्णय मांग, देशी तेलों की उपलब्धि और कुछ अन्य पहलुओं के आधार पर किया जाता है।

(ग) कोई ऐसी तकनीकी समिति गठित नहीं की गई है।

पन्ना (मध्य प्रदेश) में हीरे की खदानें

814. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रभावशील होने के बाद पन्ना में उथली हीरा खदानें खुदाई के लिये बंद कर दी गयी है तथा मध्य प्रदेश सरकार ने इन खदानों के पट्टे देना बंद कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप कितने खदान मजदूर बेरोजगार हो गये हैं ; और

(ग) क्या पन्ना के हीरा खदान क्षेत्रों में वन न होने के बावजूद भी वहां वन संरक्षण अधिनियम के उपबन्धों को लागू कर दिया गया है और यदि हां, तो इस क्षेत्र में इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के क्या कारण है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) (क) से (ग) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

Utilisation of water from Chambal Canal by Madhya Pradesh and Rajasthan

815. SHRI PYARELAL KHANDELWAL: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) what is the proportion in which Madhya Pradesh and Rajasthan have utilised water from Chambal Canal each year from 1977-78 to 1984-85;

(b) whether it is a fact that Madhya Pradesh is not getting adequate share of water;

(c) if so, what is the reason therefor;

(d) whether it is also a fact that a field agency for water regulation as decided by M.P. and Rajasthan Interstate Control Board has not yet been set up; and

(e) if so, what are the reasons therefor and the steps taken for its early constitution?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI B. SHANKARANAND): (a) It is reported that the States of Madhya Pradesh and Rajasthan have utilised water from the common Chambal Right Main Canal System, as given below:—

(In Million Acre Feet)

Year	Rajasthan	Madhya Pradesh
1977-78	0.9780	1.3620
1978-79	1.1634	1.3790
1979-80	0.9230	1.0520
1980-81	1.00	1.1980
1981-82	1.00	1.4571
1982-83	1.00	1.1764
1983-84	1.0861	0.8905
1984-85	1.0964	1.1723